ISSN: 2456-043X
International Journal of Engineering Science and Generic Research (IJESAR)
Available Online at www.ijesar.in
Journal Index In ICI World of Journals - ICV 2016 – 68.35
Volume 9; Issue 5; September-October; 2023; Page No. 1-9

भारत में शरणार्थियों की समस्या का अध्ययन

Kirti Yadav, Research Scholar, Monad University, Hapur

Dr. Pravin Kumar Chauhan, Associate Professor, Monad University, Hapur

अमूर्त

आधुनिक दुनिया में अस्तित्व के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा, आतंकवाद, नस्लीय-धार्मिक संघर्ष, अंतर-राज्य युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और शक्तिशाली लोगों द्वारा क्षेत्रों पर जबरन कब्जे के कारण बड़े पैमाने पर आबादी का अपनी जड़ों से अलग निकटवर्ती या दूर-दराज के स्थानों की ओर पलायन हुआ है। इसका कारण सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कोई भी हो सकता है। इस प्रकार शरणार्थियों की समस्या उभर कर सामने आती है। हालाँकि विदेशी भूमि पर शरण लेने का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान समय में दुनिया के कई देश शरणार्थियों की समस्या का सामना कर रहे हैं।

कीवर्ड. शरणार्थियों, समस्याँकिए भूमि

परिचय

प्राचीन काल से ही लोग कई कारणों से अपने मूल देश से दूसरे देश में जाते रहे हैं। कभी-कभी, यह स्वैच्छिक या जानबूझकर होता है और कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। स्वैच्छिक आंदोलन को प्रवासन के रूप में जाना जाता है और व्यक्ति को अपने मूल देश या राष्ट्रीयता से बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है बल्कि वह अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूसरे देश में चला जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रवासियों को उनके राज्यों की सुरक्षा प्राप्त है। एक और परिदृश्य है जहां किसी व्यक्ति को अपने जीवन के खतरे या असुरक्षा के कारण अपने मूल देश या राष्ट्रीयता से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे देश में शरण ले लेता है और शरणार्थी बन जाता है। सामान्य अर्थ में शरणार्थी का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने घर से भागना चाहता है जिसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। किसी व्यक्ति के भागने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे, उत्पीड़न से भागना, जान को खतरा होने से भागना, उत्पीड़न से भागना, गरीबी की मार झेलना, युद्ध या नागरिक संघर्ष से भागना, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि से भागना। शरणार्थी शब्द इस धारणा की मांग करता है कि संबंधित व्यक्ति योग्य है और उसे सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा पलायन के परिणामों से बचाया जाना चाहिए।

कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 के तहत शरणार्थी की परिभाषा उन बुनियादी तत्वों को निर्धारित करती है जिसके तहत राज्य यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति शरणार्थी है या नहीं। यह शरणार्थी की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है।2 वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (इसके बाद यूएनएचसीआर) क़ानून और 1951 कन्वेंशन में श्शरणार्थीश् शब्द की बहुत समान परिभाषा है।1 1951 के जिनेवा कन्वेंशन का उद्देश्य संशोधित करना था और शरणार्थियों पर सभी पिछले द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समेकित करना और शरणार्थी शब्द को परिभाषित करना लक्ष्य है। कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 ष्शरणार्थीष् शब्द को दो श्रेणियों में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1ए(ए) शरणार्थियों की विशिष्ट श्रेणियों की सुरक्षा के लिए पहले की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं से प्राप्त शरणार्थियों की पहली श्रेणी को संदर्भित करता है। इस श्रेणी में कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के तहत शरणार्थी कहा गया है।पहले के शरणार्थी दस्तावेज़ों में विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक शरणार्थी परिभाषाएँ शामिल थीं और केवल

पहचान और यात्रा दस्तावेजों के प्रावधान के साथ। पहली श्रेणी में, आम तौर पर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत शरणार्थी और अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संगठन (आईआरओ) संविधान के तहत शरणार्थी शामिल हैं। इस श्रेणी के शरणार्थी आम तौर पर अधिनायकवादी शासन के शिकार या युद्ध के शिकार थे। दूसरी ओर, कन्वेंशन का अनुच्छेद 1(ए)(2) शरणार्थियों की दूसरी श्रेणी को उनके गृह देश में सताए जाने के सुस्थापित भय के मानदंडों के आधार पर इस प्रकार परिभाषित करता हैरू कोई भी व्यक्ति जोरू (ए)एस 1 जनवरी 1951 से पहले घटित घटनाओं के परिणाम और जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण सताए जाने के उचित भय के कारण, अपनी राष्ट्रीयता के देश से बाहर है और असमर्थ है या, इसके कारण इस तरह के डर से, वह उस देश की सुरक्षा का लाभ उठाने को तैयार नहीं है; जो, ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीयता नहीं होने और अपने पूर्व अभ्यस्त निवास के देश से बाहर होने के कारण, असमर्थ है या ऐसे डर के कारण, वहां लौटने को तैयार नहीं है।

साहित्य और समीक्षा

शेख, तराज़ी और कोइराला, अनुरोध। (2023)।शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण हैं, फिर भी वे सबसे विवादास्पद भी हैं। 1951 में इसकी स्थापना के बाद से, संभवतः शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन के समर्थन के बाद, अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून (आईआरएल) के प्राथमिक अध्ययन में कई बदलाव हुए हैं। विशेष रूप से शरणार्थी संकट में शामिल राज्यों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के संदर्भ में, समय के साथ कई बदलाव हुए हैं। हालाँकि, काफी हद तक, शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा को नियंत्रित करने के संदर्भ में राज्यों की जिम्मेदारियों का अंतर्निहित प्रश्न भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों के बीच संबंधित जिम्मेदारियों के निर्धारण में निहित है। इस पेपर का उद्देश्य दक्षिण एशिया में शरणार्थी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित राज्यों की जिम्मेदारियों के अध्ययन में वर्तमान और पूर्ववर्ती बदलावों को ट्रैक करना है। इसके बाद यह संशोधनों के निहितार्थ और प्रभावों का आकलन करते हुए अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून के शासन में पूर्वव्यापी अध्ययन लागू करता है।

किरोंस्का, क्रिस्टीना और वर्मा, मोनिका। (2023)।यह एक लेख का प्रीप्रिंट है जिसमें भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति भारतीय आबादी के दृष्टिकोण पर शोध किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि किस नीति विकल्प को प्राथमिकता दी जाती है। इस पेपर का डेटा सिनोफोन बॉर्डरलैंड्स इंडो-पैसिफिक सर्वे (2022) से लिया गया है, जो लेखकों में से एक द्वारा आयोजित एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सर्वेक्षण है। इसके अतिरिक्त, लेखकों में से एक ने प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए भारत में रहने वाले रोहिंग्या व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए।

गोविंदराज, योगानंदम। (2023)।प्रवासन एक चिंता का विषय है क्योंकि वैश्विक स्तर पर 184 मिलियन प्रवासी हैं, जिनमें से 43 प्रतिशत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासन को प्रबंधित करने के तरीकों के रूप में वित्तीय और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने, बाधाओं को कम करने और सरकारी प्रतिक्रियाओं में सुधार करने का सुझाव देती है। मूल देश विकास का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, लेकिन गंतव्य देश इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बढ़ती आबादी और कम आय वाले देश प्रवासन को बढ़ावा देते हैं, जिससे वैश्विक श्रम बाजार प्रभावित होता है। नीति निर्माताओं को आप्रवासन को प्रवासियों की प्रतिभा के साथ जोड़ना चाहिए और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दशक में, संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण शरणार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई। आर्थिक प्रवासन और जबरन स्थानांतरण पैटर्न अलग-अलग हैं, जिनमें कमजोर व्यक्तियों की संख्या 41ः है। नीति निर्माता प्रवासियों की सुरक्षा के लिए मैच एंड मोटिव मैट्रिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग कर सकते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 श्रम बाजार अंतराल के समाधान के रूप में आप्रवासन पर जोर देती है, लेकिन

सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्षों पर भी जोर देती है। भेदभाव रहित कानूनों और आर्थिक समावेशन के माध्यम से एकीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन समान प्रतिभाओं से नौकरी छूट सकती है, शिक्षा और गरीबी में कमी आ सकती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जलवायु परिवर्तन असंतुलन को संबोधित करना आवश्यक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर, इस शोध लेख का मुख्य उद्देश्य सूचना के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के साथ-साथ प्रासंगिक सांख्यिकीय डेटा का उपयोग करके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से भारत के संबंध में वैश्विक सहयोग, प्रवासन, सामाजिक चुनौतियों और आप्रवासी अधिकारों का विश्लेषण करना है। लेख का विषय. लेख का विषय वैश्विक स्तर पर 184 मिलियन प्रवासी हैं, जिनमें से 43ः निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जिससे प्रवासन एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बन गया है।वित्तीय अंतराल, नौकरी की संभावनाओं, जनसांख्यिकीय बदलाव और जलवायु खर्चों के परिणामस्वरूप प्रवासन संबंधी चिंताएँ अधिक व्यापक हो रही हैं। प्रवासन आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में मदद करता है, लेकिन यह जटिलताएँ और जोखिम भी लाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 आर्थिक और वित्तीय संभावनाओं पर जोर देने और प्रवासियों की बाधाओं को कम करने के साथ गंतव्य, पारगमन और मूल देशों में प्रवासन के प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण सुझाती है। श्रम अर्थशास्त्र और प्रवासन कारणों पर ध्यान देने के साथ, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 मैच-मकसद दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रवासन व्यापार-बंद का आकलन करती है। यह दृष्टिकोण प्रवासियों के अवसरों और लाभों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या बहुपक्षीय कार्रवाइयों के माध्यम से नीतिगत प्रतिक्रियाओं में सुधार करने का सुझाव देता है। प्रेषण प्रवाह को प्रोत्साहित करके, शैक्षिक संभावनाओं को बढ़ाकर, निवेश को प्रोत्साहित करके और लौटने वाले प्रवासियों को सहायता प्रदान करके, मूल राष्ट्र श्रम प्रवास के विकास लाभों को अधिकतम कर सकते हैं। गंतव्य राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक नतीजों को संबोधित कर सकते हैं, दीर्घकालिक श्रम बाजार की मांगों को पूरा कर सकते हैं और प्रवासियों के साथ मानवीय व्यवहार कर सकते हैं।परेशान प्रवासन को कम करने और शरणार्थियों की मेजबानी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए, पारगमन देशों को गंतव्य देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। इस पेपर में चर्चा किया गया शोध प्रवासन से जुड़ी चुनौतियों और जटिलता का एक उदाहरण है। यह निर्णय लेने वालों को सूचित विकल्प बनाने और उपयोगी सांप्रदायिक और व्यक्तिगत पहलों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। समस्या का विवरण तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बढ़ती आबादी और कम आय वाले देशों में जनसंख्या विस्तार, सभी प्रवासन की बढ़ती आवश्यकता में योगदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक श्रम बाज़ार अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। विश्व में रहने वाले 184 मिलियन व्यक्तियों में से 37 मिलियन शरणार्थी हैं, जिनमें से 43ः परिवार निम्न और मध्यम आय वाले हैं। गंतव्य देशों की आवश्यकताओं और आप्रवासन लक्ष्यों को प्रवासियों की प्रतिभा और विशेषताओं के साथ संरेखित करने के लिए, लेख नीति निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले देशों सहित गंतव्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फायदे और दायित्वों को निर्धारित करता है। नीति निर्माता मैच और उद्देश्य संरचना की सहायता से उचित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जबकि एक खराब मैच के लिए बहुपक्षीय लागत साझाकरण और शरणार्थी मेजबानी खर्चों को कम करने की आवश्यकता होती है, एक मजबूत मैच प्रवासियों और उनके संबंधित देशों के पक्ष में होता है। अधिकतम लाभ।

वेलेंट्ज़ा, क्रिस्टीना। (2022)। भारत में शरणार्थी कानूनरू अस्पष्टता से सुरक्षा तक का मार्ग एक दिलचस्प पाठ है। न केवल भारत में शरणार्थियों और प्रवासियों पर नीति, कानूनी और नियामक पहलुओं में रुचि रखने वालों के लिए, बल्कि सामान्य रूप से शरणार्थी संरक्षण, मानदंडों और नीतियों में रुचि रखने वालों के लिए और देश के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित आबादी पर मानवाधिकार अभ्यास में काम करने वालों के लिए भी। दुनिया। पुस्तक में आठ अध्याय हैं (भारत में शरणार्थियों की सुरक्षा और कानूनी स्थितियों का दर्शन, भारत में शरणार्थियों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिक्रिया, संसदीय कार्यवाही, शरणार्थियों के प्रति

मानवाधिकार आयोग और संस्थानों की प्रतिक्रिया, भारत में शरणार्थियों की स्थिति पर एक क्षेत्रीय अध्ययन, शरणार्थी सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और कनाडा के राष्ट्रीय शरणार्थी कानून पर एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत के लिए शरणार्थी कानून की कल्पना और अंत में, एक नए कानून की मांग)

वखोनेवा, तेत्याना और मायकोलायेट्स, दिमित्रो और ह्रीशिना, यूलिया और युरोव्स्का, विक्टोरिया और डायचेन्को, ओल्हा। (2023)।शरणार्थी का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की समस्या की प्रासंगिकता, विशेष रूप से, इस तथ्य के कारण है कि शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि और संबंधित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं कानूनी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार की आवश्यकता की पुष्टि करती हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर शरणार्थी समस्या के विश्लेषण और समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करना। यूक्रेन की स्थिति इस तथ्य की भी पुष्टि करती है कि सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के ढांचे के भीतर सहयोग करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा का मुद्दा वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रासंगिकता नहीं खोता है। लेख का उद्देश्य शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने की सामान्य विशेषताओं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा काम करने के अधिकार के प्रयोग का अध्ययन करना है। लेखक प्रासंगिक विषयों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के मानक स्रोतों का विश्लेषण करता है। इसके अलावा, लेखक शरणार्थियों द्वारा काम करने के अधिकार के प्रयोग के व्यावहारिक पहलुओं, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की जांच करता है और मौजूदा समस्याओं के संभावित समाधान सुझाता है। अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि औपचारिक कानूनी विधि है। इसके अनुप्रयोग ने अध्ययन की व्यवहार्यता और वैधता निर्धारित की। इस पद्धति का उपयोग शरणार्थियों के श्रम अधिकारों की सुरक्षा को विनियमित करने वाले कानूनी कृत्यों के विश्लेषण में किया गया था, अर्थात्रू अंतरराष्ट्रीय कानून के अधिनियम, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, एशियाई देशों के कानून, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रीय कानून।

भारत में शरणार्थी पहचान की चुनौतियाँ

भारत ने बार-बार शरणार्थी सुरक्षा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत दिया है और फिर भी शरणार्थी मान्यता की इसकी दोहरी प्रणाली एक जटिल सुरक्षा तस्वीर प्रस्तुत करती है।

एक दुर्लभ दोहरी प्रणाली में, भारत में शरणार्थी स्थिति निर्धारण (आरएसडी) सरकार और यूएनएचसीआर के बीच विभाजित है। गैर-पड़ोसी देशों और म्यांमार से आने वाले शरण चाहने वालों को अपनी स्थिति के निर्धारण और दस्तावेज़ीकरण के लिए यूएनएचसीआर से संपर्क करना आवश्यक है। भारत में यूएनएचसीआर 1951 शरणार्थी कन्वेंशन (जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है) और अपने स्वयं के आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनके लिए आरएसडी आयोजित करता है, शरण चाहने वालों और शरणार्थियों की सूची को गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ साझा करता है। हालाँकि, यह तथ्य कि यूएनएचसीआर को सीमाओं पर पंजीकरण केंद्र स्थापित करने की अनुमति नहीं है, आने वाले शरण चाहने वालों पर शरण प्रक्रिया के बारे में पता लगाने और नई दिल्ली की यात्रा करने का दायित्व है - यूएनएचसीआर भारत का एकमात्र कार्यालय है जो आरएसडी का संचालन करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। सेवाएँ - दावा करने के लिए।

पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के लोगों, जिनके साथ राज्य के संवेदनशील संबंध हैं, को सीधे गृह मंत्रालय से संपर्क करना आवश्यक है। ऐसा करने की प्रक्रिया और ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा अपनाए गए निर्णय मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अतीत में, तिब्बती और श्रीलंकाई (क्रमशः 1955 और 1984 से) जैसे महत्वपूर्ण संख्या में आने वाले शरणार्थियों को सरकार द्वारा शिविरों और बस्तियों में अस्थायी सुरक्षा की पेशकश की गई थी, और इन शरणार्थियों के इलाज के लिए भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। हालाँकि, हाल के आगमन के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए छिटपुट आंतरिक निर्देशों के

अलावा, सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति दिशानिर्देश नहीं हैं।

1. विधायी ढांचा

एक परिभाषित कानूनी ढांचे के अभाव में, भारत में शरणार्थी संरक्षण पारंपरिक रूप से मनमानी कार्यकारी नीतियों, पूरक कानून और न्यायिक घोषणाओं पर आधारित रहा है। हाल तक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए प्रासंगिक एकमात्र कानून 1946 का विदेशी अधिनियम और 1967 का पासपोर्ट अधिनियम था, जो विदेशियों (गैर-नागरिकों के रूप में परिभाषित) के प्रवेश, रहने और निकास को नियंत्रित करता है। दुर्भाग्य से, ये कानून अवैध प्रवेश और प्रवास के लिए विदेशियों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की व्यापक शक्तियाँ देते हैं, और शरणार्थियों के लिए कोई अलग व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे वे भी हिरासत और निर्वासन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

समर्पित कानून के अभाव में, भारतीय अदालतों ने कुछ मामलों में प्रथम दृष्टया शरण के दावे वाले बंदियों को आरएसडी के लिए यूएनएचसीआर से संपर्क करने की अनुमति दी है। हालाँकि, यह नियम के बजाय अपवाद है, और ऐसे हस्तक्षेप किसी निर्धारित मानदंड द्वारा शासित नहीं होते हैं बल्कि मामला-दर-मामला आधार पर किए जाते हैं। इसके अलावा, यह प्रक्रिया तब और जटिल हो जाती है जब शरण चाहने वाला उन देशों में से एक से होता है जहां शरण के दावे भारत सरकार के आदेश के तहत आते हैं, क्योंकि यूएनएचसीआर के पास ऐसे शरण दावों पर निर्णय लेने के लिए कोई निर्दिष्ट प्राधिकारी नहीं है। परिणामस्वरूप, इस समूह के देशों के शरण चाहने वालों के हिरासत में रहने की और भी अधिक संभावना हो सकती है, क्योंकि उनके पास शरण का दावा करने के लिए रास्ते की कमी है।

जिन लोगों को यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाती है, उन्हें एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, लेकिन इन्हें राज्य के अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है (सरकार द्वारा इसके जनादेश के तहत आने वाले शरणार्थियों को जारी किए गए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज के विपरीत)।

इसलिए यूएनएचसीआर द्वारा सम्मानित शरणार्थी का दर्जा शरणार्थियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है क्योंकि उनके दस्तावेज़ों की मान्यता की कमी का मतलब है कि वे हमेशा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या अन्य बुनियादी अधिकारों तक नहीं पहुंच सकते हैं। यूएनएचसीआर या भारत में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता की व्यापक कमी के कारण, यूएनएचसीआर द्वारा जारी दस्तावेज वाले लोगों को अक्सर अधिकारियों द्वारा अवैध निवासियों के रूप में देखा जाता है।

विशेष रूप से, भारतीय अदालतों ने वर्षों से आगे आकर शरणार्थियों को श्विदेशियोंश् के एक विशिष्ट वर्ग के रूप में मान्यता दी है, और उन्हें बुनियादी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शरणार्थियों को जीवन और समानता का अधिकार दिया, भले ही एक सीमित सीमा तक। न्यायालयों ने आव्रजन अधिकारियों को निर्वासन मामलों में उचित प्रक्रिया सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और आरएसडी का संचालन करने और बंदी के शरण दावे का निर्धारण करने के लिए यूएनएचसीआर से हस्तक्षेप की मांग की है। और, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पूरक कानूनों को लागू करके, जो सभी बच्चों (कानूनी स्थिति की परवाह किए बिना) को सरकारी स्कूलों में नामांकित करने की अनुमति देता है, शरणार्थियों को आवश्यक सामाजिक-आर्थिक अधिकारों तक पहुंच की अनुमति दी गई है। हालाँकि, इस प्रकार की अधिकांश न्यायिक घोषणाएँ निचली अदालतों से आई हैं और उनका सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा निर्धारित मिसाल के समान मूल्य नहीं है; इसके अलावा, अधिकांश मामले-विशिष्ट हैं और उन्हें सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। शरणार्थी प्रबंधन पर एक कानून शरणार्थियों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में अदालत के फैसले से कहीं आगे जाएगा।

2. भारत और जीसीआर

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, शरणार्थियों पर 2018 ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी (जीसीआर) का

भारत का निर्बाध समर्थन एक स्वागत योग्य प्रतिबद्धता थी। हालाँकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन नहीं है (जिसने निश्चित रूप से भारत सहित कई देशों द्वारा स्वीकार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है), जीसीआर शरणार्थी सुरक्षा के लिए कुछ प्रकार की श्इच्छा सूचीश् प्रदान करता है, जिसके खिलाफ सरकारों को बुलाया जा सकता है। खाता। हालांकि इसमें आरएसडी के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जीसीआर में शरणार्थियों की पहचान और पंजीकरण और व्यक्तिगत शरण दावों के निष्पक्ष और कुशल निर्धारण के लिए तंत्र की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अधिक ठोस रूप से, इसने न्छभ्ब्त् को उन राज्यों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक शरण क्षमता सहायता समूह की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया जो इसका अनुरोध करते हैं, ताकि उनकी शरण प्रणाली को निष्पक्षता, दक्षता, अनुकूलनशीलता और अखंडता प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह यूएनएचसीआर की बार-बार दोहराई जाने वाली स्थिति का स्पष्ट बयान है कि आरएसडी राज्य की संप्रभु शक्ति के प्रयोग का हिस्सा है और यूएनएचसीआर का उद्देश्य जहां भी संभव हो राष्ट्रीय शरण निर्धारण प्रणालियों को सुविधाजनक बनाना है।

हालाँकि, अब तक, भारत सरकार ने उन आरएसडी कार्यों को लेने का कोई ज्ञात इरादा व्यक्त नहीं किया है जो वर्तमान में यूएनएचसीआर द्वारा किए जाते हैं, और यूएनएचसीआर को दोनों पक्षों के बीच मौजूद समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत अपनी प्रक्रियाओं का संचालन करने की अनुमति देता है। वास्तव में, राजनीतिक स्तर पर और आम जनता के बीच शरणार्थी मुद्दों की सामान्य उपेक्षा को देखते हुए, अगस्त 2017 में जारी निर्वासन आदेश - जिसमें भारत के भीतर सभी रोहिंग्याओं के बड़े पैमाने पर निर्वासन का आह्वान किया गया था - बिना किसी चेतावनी के आया। इसमें म्यांमार से आने वाले लोगों के रूप में यूएनएचसीआर शरणार्थी स्थिति तक उनकी पहुंच का कोई जिक्र नहीं किया गया, न ही उन शरणार्थियों के बीच अंतर किया गया जिन्हें पहले ही मान्यता दी जा चुकी थी और जिन्हें अभी तक यूएनएचसीआर द्वारा दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे। इससे यह भी प्रदर्शित हुआ कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त शरणार्थी दर्जे को बहुत कम कानूनी महत्व देती है

भारत के नागरिकता कानूनों में दिसंबर 2019 में किए गए संशोधनों के मद्देनजर शरणार्थी मुद्दे हाल ही में सार्वजनिक चर्चा के दायरे में सामने आए, जिसने देश भर में नागरिक नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। नया कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को छोड़कर सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, जो सरकारी-आदेश और यूएनएचसीआर-आदेश शरणार्थियों दोनों को प्रभावित करता है। विडंबना यह है कि यह शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला कानून है। हालाँकि, संशोधनों ने शरणार्थी का दर्जा देने के मानदंडों को भी स्पष्ट नहीं किया और परिणामस्वरूप, शरण प्रबंधन और आरएसडी प्रक्रियाएं अस्पष्टता में डूबी हुई हैं।

यूएनएचसीआर-जनादेश आरएसडी प्रक्रिया को सरकार द्वारा दी गई वैधता का क्षरण भी सुरक्षा स्थितियों में सामान्य गिरावट का प्रमाण है। जहां पहले यूएनएचसीआर-जनादेश शरणार्थियों को भारत की विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रोजगार मिल सकता था, हाल के वर्षों में सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों के बिना व्यक्तियों को रोजगार देने पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह तेजी से कठिन हो गया है; इसी तरह, घर किराए पर लेना या सिम कार्ड खरीदने जैसी साधारण आर्थिक गतिविधियां भी लगभग असंभव हो गई हैं। जबकि 2012 में सरकार ने यूएनएचसीआर-जनादेश शरणार्थियों को एक विशेष श्रेणी के वीज़ा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी, जिसे लॉन्ग टर्म वीज़ा कहा जाता है, जो धारक को तृतीयक शिक्षा तक पहुंचने और निजी क्षेत्र में नियोजित होने की अनुमति देता है, इसे जारी करना मनमाना और गंभीर रूप से प्रतिबंधित है, और वहाँ है शरणार्थियों को अन्य प्रकार के दस्तावेज़ों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो उनके दैनिक जीवन को सरल बना देगा।

ये घटनाएँ, जो पिछले तीन वर्षों में घटी हैं, हमारे अनुभव और आरएसडी रुझानों के विश्लेषण के अनुसार, नई दिल्ली यूएनएचसीआर कार्यालय की ओर से आरएसडी के प्रति अधिक सतर्क दृष्टिकोण के साथ मेल खाती हैं, जिसका पहचान दर में लगातार कमी आई है और शरणार्थियों की संख्या में किसी भी आनुपातिक वृद्धि के बिना, केस-प्रोसेसिंग की समय-सीमा बहुत लंबी हो गई है।

इस पृष्ठभूमि में, ब्व्टप्क्-19 महामारी ने भारत में त्ैक् को ठप्प कर दिया है। लेखन के समय संक्रमण चिंताजनक दर से बढ़ रहा है, वर्तमान में किसी भी समय महामारी-पूर्व स्तर पर पंजीकरण और आरएसडी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की संभावना कम लगती है। इससे कई शरणार्थियों को हिरासत और निर्वासन के खिलाफ बुनियादी सुरक्षा तक भी पहुंच नहीं मिलेगी जो यूएनएचसीआर-जनादेश दस्तावेज़ द्वारा प्रदान की जाती है। अंतरिम में, वास्तविक आवश्यकता भारत सरकार के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वकालत दोनों की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपनी जीसीआर प्रतिबद्धताओं और मानवीय दायित्वों पर कायम रहे।

3. कोविड-19 महामारी के दौरान शरणार्थियों की दुर्दशा

यूएनएचसीआर बहुत कम संख्या में मान्यता प्राप्त शरणार्थियों को उनकी असाधारण सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकलांगता और उम्र संबंधी चिंताओं के आकलन के आधार पर नकद आधारित सहायता (सीबीए) प्रदान करता है। सीबीए राशि और अवधि में सीमित है। यूएनएचसीआर और उसके साझेदार शरणार्थियों को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यूएनएचसीआर साझेदार शिक्षा, व्यावसायिक और भाषा प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता से संबंधित कार्यक्रम पेश करते हैं। हालाँकि, विदेशी होने के कारण, वे कानूनी रूप से वर्क परमिट के हकदार नहीं हैं और आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण, उन्हें संगठित या औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल सकता है। अधिकांश चिन शरणार्थी पश्चिमी दिल्ली में अपंजीकृत कारखानों में काम करते हैं, जबकि अन्य रेस्तरां, घरों में सहायक के रूप में, घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं या जहां वे रहते हैं वहां और आसपास की कॉलोनियों में सब्जियां बेचते हैं। चिन के लिए भाषा सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि म्यांमार से आए लोगों में से मुश्किल से 10श् अंग्रेजी या हिंदी बोल सकते हैं, हालांकि दिल्ली में पैदा हुए बच्चे हिंदी में पारंगत हैं। हिंदी बोलने और समझने में उनकी असमर्थता अक्सर फैक्ट्री मालिकों द्वारा शोषण का कारण बनती है। सामाजिक लाभों के अभाव और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, शरणार्थियों को विशेष रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान परेशानी उठानी पड़ी।

नागरिकता अधिकारों और सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाणों की कमी के कारण, वे आसानी से सब्सिडी वाले भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और ऐसे अन्य लाभों तक नहीं पहुंच पाते। ब्व्टप्क्-19 लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के शरणार्थियों को रोजगार के नुकसान का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में कई रोहिंग्या शरणार्थियों के भूख से मरने की खबर है क्योंकि लॉकडाउन के बाद से उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा है। दूसरी ओर, दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी आधिकारिक मान्यता की कमी के कारण दिल्ली सरकार की आजीविका सहायता योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं। यही हाल अफ़ग़ान शरणार्थियों का है, जिनकी आजीविका लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है. अगस्त 2021 में रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (आरएचआरआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत भर में रहने वाले लगभग 56 रोहिंग्या शरणार्थियों ने महामारी के कारण रोजगार खो दिया। नई दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर के 40 स्थानों से 65 महिलाओं सहित लगभग 120 रोहिंग्या शरणार्थियों का आरएचआरआई द्वारा कोविड-19 आपातकालीन स्टेटलेसनेस फंड पर रिपोर्ट के लिए सर्वेक्षण किया गया था।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आय के रास्ते खोने के अलावा, सूचीबद्ध सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाणों के अभाव में, शरणार्थी न तो मुफ्त भोजन राशन, न ही मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और न ही भारत में कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं। महामारी की दूसरी लहर के दौरान कम से कम छह चिन शरणार्थियों की कोविड-

19 संक्रमण के कारण मौत हो गई, अक्सर सरकारी अस्पतालों में बिना किसी चिकित्सा देखभाल के, क्योंकि उनके पास निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिए आवश्यक दस्तावेज या धन की कमी थी। ब्ब्टप्क्-19 के टीकाकरण के लिए, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके ब्वॅपद प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है। शरणार्थी विशेष रूप से गैर-मान्यता प्राप्त और गैर-दस्तावेजी शरणार्थी इन दस्तावेजों के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, उच्च लागत के कारण निजी स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच से बाहर हैं। दरअसल, शरणार्थियों के लिए एकमात्र सहायता प्रणाली, यूएनएचसीआर और उसके सहयोगियों के कार्यालय, सीओवीआईडी -19 के प्रकोप के बाद 21 मार्च 2020 से बंद कर दिए गए थे और वे दूर से काम कर रहे थे, जिससे शरणार्थी बेहद असुरक्षित हो गए थे।

निष्कर्ष

लोगों का अपनी ही भूमि से विस्थापन और उनका अन्यत्र आत्मसात होना मानव जाति की कहानी की एक कभी न खत्म होने वाली विशेषता रही है। वास्तव में, वे राष्ट्रीय सुरक्षा और दर्जा प्राप्त करने वाले, विस्थापित, बेघर व्यक्ति हैं, जो अपने मूल देश, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय को छोड़कर दूसरे देश में शरण या शरण चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट, मानवाधिकारों का उल्लंघन और युद्ध पहले से कहीं अधिक लोगों को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रवासन का दबाव बढ़ जाता है और दुनिया भर में शरणार्थियों और विस्थापितों का प्रवाह बढ़ जाता है। यह सत्य है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना शरणार्थियों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शरणार्थी संकट जो अब दुनिया के सभी हिस्सों में व्याप्त है, के अपने कारण और स्पष्टीकरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक उत्पीड़न का डर है जो व्यक्ति को अपने ही देश में झेलना पड़ता है।

संदर्भ

1. शेख, तराज़ी और कोइराला, अनुरोध। (2023)। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून में राज्यों की जिम्मेदारियाँरू दक्षिण एशिया में एक पूर्वव्यापी अध्ययन। 11. 6-24.
2. किरोंस्का, क्रिस्टीना और वर्मा, मोनिका। (2023)। भारत में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों पर जनता की राय तलाशनारू एक अनुभवजन्य अध्ययन। 10.13140/आरजी.2.2.27665.61283।
3. गोविंदराज, योगानंदम। (2023)। वैश्विक सहयोग, प्रवासन, सामाजिक चुनौतियाँ, और भारत के संबंध में आप्रवासी अधिकार - एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। 11. 2455-6211.
4. वेलेंट्ज़ा, क्रिस्टीना। (2022)। ष्पुस्तक समीक्षारू भारत में शरणार्थी कानूनरू अस्पष्टता से सुरक्षा तक का मार्ग, एस. पी. सरकारष् अब एशियन जर्नल ऑफ लीगल एजुकेशन के खंड 9, अंक 2 में प्रकाशित हुआ है।
5. वखोनेवा, तेत्याना और मायकोलायेट्स, दिमित्रो और ह्रीशिना, यूलिया और युरोव्स्का, विक्टोरिया और डायचेन्को, ओल्हा। (2023)। डिजिटल युग में शरणार्थियों के श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी चुनौतियाँ। वैधानिकतारू जर्नल इल्मिया हुकुम। 31. 245-265. 10.22219/सरपी.अ31प2.26576.
6. सुप्रियादी, स्लैमेट। (2022)। मानवाधिकारों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थीरू अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और मानवाधिकार कानून पर एक प्रवचन। दक्षिण पूर्व एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवचन। 1.43-64. 10.15294/पसकपेमं.अ1प1.56872.
7. फेरिस, ई.जी., द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेक्शनरू द लिमिट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन, 2011।
8. फ्रैट्ज़के, सुसान, नॉट एडिंग अपरू द फ़ेडिंग प्रॉमिस ऑफ़ यूरोप्स डबलिन सिस्टम, माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूरोप, 2015।
9. गैट्रेल, पीटर, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न रिफ्यूजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूके, 2013।

10. हैमरस्टेड, ऐनी, द राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ़ ए ग्लोबल सिक्योरिटी एक्टररू यूएनएचसीआर, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूके, 2014।
11. शरणार्थी की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रक्रियाओं और मानदंडों पर हैंडबुक और दिशानिर्देशरू शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन और 1967 प्रोटोकॉल के तहत, यूएनएचसीआर, जिनेवा, 2011 द्वारा प्रकाशित।
12. जस, सतविंदर सिंह और कॉलिन हार्वे, शरणार्थी कानून में समकालीन मुद्दे, एडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग लिमिटेड, यूके, 2013।
13. कमिंसकी, अर्नाल्ड पी. और रोजर डी. लॉन्ग (संस्करण), इंडिया टुडेरू एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ इन द रिपब्लिक (खंड 1), लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कैलिफोर्निया, 2011।
14. इस्लाम, एम. रफीकुल और मोहम्मद जाहिद इओसैन भुइयां (संस्करण), एन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ, मार्टिनस निजॉफ पब्लिशर्स, द नीदरलैंड्स, 2013।
15. हैमरस्टेड, ऐनी, द राइज़ एंड डिक्लाइन ऑफ़ ए ग्लोबल सिक्योरिटी एक्टररू यूएनएचसीआर, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूके, 2014

Aadhunik duniya mein astitv ke lie bhayankar pratispardha, aatankavaad, nasleey-dhaarmik sangharsh, antar-raajy yuddh, praakrtik aapadaon aur shaktishaalee logon dvaara kshetron par jabaran kabje ke kaaran bade paimaane par aabaadee ka apanee jadon se alag nikatavartee ya door-daraaj ke sthaanon kee or palaayan hua hai. isaka kaaran saamaajik
aarthik ya raajaneetik koee bhee ho sakata hai. is prakaar sharanaarthiyon kee samasya ubhar kar saamane aatee hai. haalaanki videshee bhoomi par sharan lene ka ek lamba itihaas raha hai, lekin vartamaan samay mein duniya ke kaee desh sharanaarthiyon kee samasya ka saamana kar rahe hain.

keevard. sharanaarthiyon, samasyaankie bhoomi